

Scheme to Rehabilitate Persons under Gadgil Assurance

1010. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7718 on the 29th May, 1972 regarding rehabilitation of displaced persons under Gadgil Assurance and state:

(a) whether the scheme to resettle 1221 families found eligible under Gadgil Assurance has since been finalised;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the time likely to be taken in finalising the scheme?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) In respect of 323 families, the Delhi Development Authority has finalised schemes to resettle them on the same sites.

(b) and (c). The Delhi Development Authority will draw up schemes for the resettlement of the remaining residential squatters after detailed physical survey and finalisation of the zonal/Implementation plans of the areas.

Groundnut Production in Gujarat

1011. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether for the last two years the groundnut production in the State of Gujarat has been much less than before; and

(b) if so, the main reasons for this?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Groundnut production in the State in 1975-76 had reached a record level of 20.3 lakh tonnes; according to the available information, output in 1976-77 is somewhat lower than that in 1975-76 but exceeds production in preceding years.

(b) Does not arise.

Panel on production of Cotton Oilseeds and Pulses

1012. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government have set up a panel to go into the problems of stepping up the production of cotton, oilseeds and pulses; and

(b) if so, the composition of the panel and date for the submission of its report?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b): The Government of India had set up a Special Group under the Chairmanship of Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture for drawing up a plan of action for increasing the production of Cotton, Edible Oilseeds and Pulses during the year 1977-78 and also suggest long term measures. The other Members of the Special Group were:

1. Director-General, ICAR & Ex-officio Secretary, Department of Agricultural Research & Education, New Delhi.

2. Secretary, Planning Commission, New Delhi.

3. Secretary, Department of Food, New Delhi.

4. Secretary, Department of Textiles, New Delhi.

5. Secretary, Department of Civil Supplies & Cooperation, New Delhi.

6. Chief Economic Adviser to the Government of India.

7. Agricultural Commissioner to the Government of India.

8. Joint Commissioner (Commercial Crops), Department of Agriculture, New Delhi.

9. Joint Commissioner (Cotton), Department of Agriculture, New Delhi.

10. Joint Commissioner (Food Corps), Department of Agriculture, New Delhi. The Special Group submitted its report on 16.5.77.

बिहार में चीनी मिलों का बन्द होना

1013. श्री कृष्णचंद झासाह वर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्र, यह बातों की कृपा करके कि :

(क) क्या बिहार में कई चीनी मिलें अनेक वर्षों से बन्द पड़ी है और इस कारण गन्ना उत्पादकों, मजदूरों आदि को अत्यधिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ तो उन मिलों के नाम क्या है, वे किस तारीख से बंद पड़ी है ; अन्येक मिल के पास चीनी का कितना अनाविका स्टॉक पड़ा है ; गन्ना उत्पादकों को कितनी बकाया राशि देनी है ; इन मिलों को पुनः चालू करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बिहार में कुल 30 चीनी फैक्ट्रियों में से 3 फैक्ट्रियां बन्द पड़ी हैं। इन फैक्ट्रियों के क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों को चीनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि उनका गन्ना क्षेत्र अन्य पड़ोस की फैक्ट्रियों को आवंटित कर दिया गया है तथा उनके द्वारा गन्ना खरीदा जा रहा है। तथापि, मजदूरों को कठिनाई हो रही है।

(ख) बिहार शुगर वर्क्स, पचरखी, जिला सिवान और सकरी शुगर वर्क्स, दरभंगा शुगर कम्पनी लिमिटेड, जिला दरभंगा 1975-76 मौसम से बन्द पड़ी है। और रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड डालमिया नगर 77-78 से बंद पड़ी है बिहार शुगर वर्क्स के पास 1974-75 और पूर्व के मौसमों में उत्पादित चीनी का लगभग 20,000 क्विंटल का बिना स्टॉक पड़ा था जिस का अब निपटान किया जा रहा है। पहले उसका निपटान रोक दिया गया था। क्योंकि एक बैंक ने अपने नियंत्रण में शक ले लिया था और उसके निपटान के लिये पग नदी उठाये गये थे। सकरी फैक्ट्री के पास चीनी का बिना बिका स्टॉक नहीं था। चीनी के स्टॉक के बारे में रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार शुगर वर्क्स को गन्ने के मूल्य के 11.22 लाख रुपये देने है और सकरी शुगर फैक्ट्री को बकाया राशि 19.14 लाख रुपये है। डालमिया नगर फैक्ट्री ने सूचित किया था कि 15.12.67 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि 0.01 लाख रुपये थी। बिहार सरकार की बिहार शुगर वर्क्स को फिर से चालू करने के लिये कोई तान्कालिक योजना नहीं है क्योंकि यह एक प्राइवेट फैक्ट्री है जिसमें एक परिवार के चार सदस्य मालिक है जिन्होंने मिले तीन वर्षों में समे अन्न चिलेना बंद कर दिया है और यह कोई पार्टी अनिश्चित निधि लगाकर इस फैक्ट्री को चलाने के लिये इच्छुक नहीं है क्योंकि फैक्ट्री को कुल लगभग दो करोड़ रुपये की भारी राशि देनी है जिसमें अन्य विविध देय राशियों के अलावा, बैंक ऋण के लगभग 1.42 करोड़ रुपये मजदूरों को देय लगभग 70 लाख रुपये और राज्य सरकार को देय कर के लगभग 20 लाख रुपये शामिल है। राज्य सरकार सकरी शुगर फैक्ट्री का स्वामित्व अपने अधिकार में लेने पर विचार कर रही है। मिल के लेने सम्बन्धी कार्यवाही पूरी होने के बाद फिर चालू करने की योजना तैयार की जायेगी। इस